GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO - 167
ANSWERED ON – 07.08.2024

IMPLEMENTATION OF PMKVY

*167 SHRI DIGVIJAYA SINGH:

Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state:-

(a) the total number of individuals trained and placed under Short-Term Training (STT) and Special Projects (SP) component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) during last three years;

(b) the total number of candidates assessed, certified and placed under the Recognition of Prior Learning (RPL) component of PMKVY during the last three years;

(c) the placement rates under PMKVY 1.0, PMKVY 2.0 and PMKVY 3.0, year-wise details thereof;

(d) the steps Government is taking to ensure improvement of placements under PMKVY 4.0; and

(e) the steps Government has taken to improve the quality of training under PMKVY 4.0?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(SHRI JAYANT CHAUDHARY)

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (E) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 167 TO BE ANSWERED ON 07.08.2024 ASKED BY SHRI DIGVIJAYA SINGH REGARDING IMPLEMENTATION OF PMKVY

(a) The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has been implementing Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) since 2015, for imparting skill development training through Short-Term Training (STT) (including Special Project) and up-skilling and re-skilling through Recognition of Prior Learning (RPL) to youth across the country. Special Projects are project-based short-term skilling initiatives that primarily meet the skilling needs of marginalized and vulnerable groups, difficult geographies and specialized training courses which are likely to be offered outside of regular short-term skilling programmes.

Under PMKVY, during the last three years, 8.25 lakh and 1.79 lakh candidates have been trained and reported placed respectively under Short Term Training (STT); 1.47 lakh and 0.26 lakh candidates have been trained and reported placed respectively under Special Projects (SP).

(b) Under RPL component of PMKVY, during the last three years, 3.54 lakh and 3.34 lakh candidates have been assessed and certified respectively. RPL provides up-skilling and re-skilling to the already employed workforce.

(c) Placement has been facilitated for candidates in the Short Term Training (STT), including Special Projects, component of the PMKVY. The reported placement rate in STT certified candidates under PMKVY 1.0 (2015-16), PMKVY 2.0 (2016-20) and PMKVY 3.0 (2020-22) was 19%, 53% and 28% respectively.

(d) PMKVY 4.0 is being implemented as a Demand-Driven scheme to skill the candidates. PMKVY 4.0 emphasizes on increasing the employability of the candidates by offering Industry Ready, Future Ready and Modern Skilling in various domains. The scheme focuses on new age and emerging courses such as Drone, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), 3D Printing, Block Chain, Mechatronics, Robotics, etc. On-the-Job Training (OJT), mandatory employability skills module, focus on upskilling, Aadhaar authenticated registration of candidates, blended delivery of courses, etc. are some of the important aspects of the scheme.

(e) The Government has taken various steps to improve the quality of training under PMKVY 4.0. Under the scheme, a national pool of 85,702 certified trainers and assessors have been created to improve the quality of training and assessment. Under PMKVY 4.0, job roles have been revised based on the industry demand. Currently, under PMKVY 4.0, around 800 National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned job roles (courses) have been approved for imparting Skill Development training across various sectors.

Further, to monitor the effectiveness of the skill training provided under PMKVY 4.0, the Ministry has launched Skill India Digital Hub (SIDH) a unified platform that integrates skilling, education, employment, and entrepreneurship ecosystems to provide a life-long array of services targeting a wide range of stakeholders. The whole training life cycle of candidates and their tracking (from enrolment to post certification follow-up), details of trainers and assessors, accreditation and affiliation of training provider and training centre is captured and monitored through the SIDH. It performs Aadhaar Authentication and De-duplication check of candidate at the time of enrolment. SIDH is also integrated with Public

Financial Management System (PFMS) platform to enable e-payments under Direct Beneficiary Transfer (DBT) for all eligible stakeholders.

In addition, details of the trained candidates are available on SIDH portal for connecting with potential employers. Through Skill India Digital Hub, candidates can have access to jobs and apprenticeship opportunities. Further, Rozgar Melas and Pradhan Mantri National Apprenticeship Melas (PMNAMs) have been organized to facilitate the placements opportunities to the certified candidates. So far, 1,578 Rozgar Melas and PMNAMs in 4,088 locations have been conducted across the country.

*****

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 167

उत्तर देने की तारीख 7 अगस्त, 2024

बुधवार, 16 श्रावण, 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई का कार्यान्वयन

***167 श्री दिग्विजय सिंह:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अल्पावधिक
प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजना (एसपी) घटक के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) घटक के अंतर्गत मूल्यांकित प्रमाणीकृत और नियोजित कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत नियोजन दर क्या-क्या है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत नियोजन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में श्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 167 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण।</u>

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) (विशेष परियोजना सहित) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करना है। विशेष परियोजनाएं परियोजना-आधारित अल्पावधि कौशल पहलें और नियमित अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों के अलावा पेश किए जाने वाले संभावित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं, जो मुख्य रूप से सीमांत तथा कमजोर समूहों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत क्रमशः 8.25 लाख और 1.79 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें नियुक्ति दी गई है; विशेष परियोजनाओं (एसपी) के अंतर्गत 1.47 लाख और 0.26 लाख अभ्यर्थियों को क्रमशः प्रशिक्षित और उन्हें नियोजित किया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई के आरपीएल घटक के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 3.54 लाख और 3.34 लाख उम्मीदवारों का आकलन और प्रमाणन किया गया है। आरपीएल पहले से कार्यरत कार्यबल को कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान करता है।

(ग) पीएमकेवीवाई के घटक विशेष परियोजनाओं सहित अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) में उम्मीदवारों के लिए नियोजन की सुविधा प्रदान की गई है। पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16), पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) और पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) के अंतर्गत एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों में सूचित नियोजन दर क्रमशः 19%, 53% और 28% थी।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 को उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने के लिए मांग-संचालित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, भविष्य के लिए तैयार और आधुनिक कौशल प्रदान करके उम्मीदवारों की नियोजनीयता बढ़ाने पर जोर देता है। यह स्कीम आधुनिक युग और उभरते पाठ्यक्रमों अर्थात ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, मेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स आदि पर केंद्रित है। कार्यरत प्रशिक्षण (ओजेटी), अनिवार्य रोजगार कौशल मॉड्यूल, कौशलोन्नयन पर ध्यान, उम्मीदवारों का आधार प्रमाणित पंजीकरण, पाठ्यक्रमों का मिश्रित वितरण आदि स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं।

(ङ) सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रशिक्षण और आकलन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योग्य और 85,702 प्रमाणित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का एक राष्ट्रीय पूल बनाया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग मांग के आधार पर जॉब रोल को संशोधित किया गया है। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 800 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित जॉब रोल (पाठ्यक्रम) स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए, मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है, जो हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करते हुए जीवनपर्यंत सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम्स को एकीकृत करता है। उम्मीदवारों के पूरे प्रशिक्षण जीवन चक्र और उनकी ट्रैकिंग (नामांकन से लेकर प्रमाणन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई तक), प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का विवरण, प्रशिक्षण प्रदाता तथा प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता और संबद्धता को एसआईडीएच के माध्यम से कैप्चर और मॉनिटर किया जाता है। यह नामांकन के समय उम्मीदवार के आधार प्रमाणीकरण और डी-डुप्लीकेशन की जाँच करता है। एसआईडीएच को सभी पात्र हितधारकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत ई-भुगतान सक्षम करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफ़एमएस) मंच के साथ भी एकीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संभावित नियोक्ताओं से संपर्क के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार जॉब और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ-साथ, प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं। अब तक देश भर में 4,088 स्थानों पर 1,578 रोजगार मेले और पीएमएनएएम आयोजित किए जा चुके हैं।

*****

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं - आप देख रहे हैं कि प्लेसमेंट का प्रतिशत बहुत कम है - क्रम वाइज पांच कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, जिनमें प्लेसमेंट सबसे अधिक है और उन ट्रेड्स के अपग्रेडेशन ऑफ स्किल की क्या व्यवस्था है?

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, I have a tough act to follow because my question has come after Nitin Gadkariji, and, of course, a senior parliamentarian is posing the question to me. Just give me a minute. I will give you the information because he has asked a specific question on the highest number of trades. Before I come to that, Sir, I would like to talk about the placement issue that he has highlighted.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It was a pointed question.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: You spoke about placement. Let me explain it because you have mentioned that the placement figures are low.

Sir, PMKVY is our flagship Scheme, and there are two main trainings that happen. One is the 'Short Term Training.' Second is the 'RPL.' So, as you can understand, half of the trainings -- total 1.48 crore people have been trained under this Scheme -- is actually RPL training (Recognition of Prior Learning). They already have a job. So we are left with half. Out of that, 41 per cent have actually been placed. Twenty-four lakh people are actually recorded 'as placed' under this Scheme, and the main thing to be noted, Sir, is that this is reported placement. The requirement under PMKVY-1, 2, and the 3rd phase was that the training partner will upload the appointment letter and three wage-slips on the SIDH portal; and then that person is reported 'placed.' That does not mean that people outside the number are not employed. They are getting gainful employment. I will point to the PLFS Survey that has just come. Sixty-one per cent of vocationally-trained young people in our country are employed. Sir, as regards the specific question he has asked, you will be happy and pleased to know that a lot of training and interest is being generated in future skills. The world economy, the structure of the economy, is changing at a fast pace. So, pan-India, in PMKVY-4, electronic and hardware. … *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is part of the answer. *...(Interruptions)...*

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, you wanted a 'trade.' I am mentioning the 'trades.' I am mentioning the specific 'job role trades' which are popular.

MR. CHAIRMAN: Yes, yes; hon. Minister.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Electronic and hardware is the most popular. Apparel, agriculture, logistics, these are all popular. And, specifically for the State of Madhya Pradesh, in electronics and hardware, two lakh people have been enrolled under PMKVY-4. In apparel, 78,000 people have been enrolled under PMKVY-4. In telecom, 77,000 people have been enrolled. I have provided some specific information. I will provide more details to the hon. M.P.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, इन्होंने marginalized and vulnerable sections के लिए भी कुछ trades अंकित किए हैं। उन trades में minimum qualification क्या है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री जयंत चौधरी: सर, इन्होंने सवाल PMKVY के बारे में पूछा है, उसके अंतर्गत भी ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is responding.

श्री जयंत चौधरी: सर, इनके संबंध मेरे पिताजी से इतने अच्छे हैं कि मैं इनके आगे बोल नहीं सकता। ये मुझे टोक रहे हैं।

श्री सभापति: ऐसा है, उस तरीके से तो मेरे संबंध आपके पिताजी से भी थे, ...(**व्यवधान**)... सुनिए, माननीय मंत्री जी, मेरे संबंध आपके पिताजी से भी हैं और मैंने आपके दादाजी से भी आशीर्वाद लिया हुआ है।

श्री जयंत चौधरी: सर, मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जन शिक्षण संस्थान योजना है। वैसे यह योजना 1967 से चल रही थी, दूसरे विभाग में संचालित थी। जन शिक्षण संस्थान मुख्य तौर पर सामाजिक संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें जो NSQF aligned Grade-4 हैं, वहाँ तक की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जन शिक्षण संस्थान में 83 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं तथा एससी और एसटी वर्ग के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के जो लोग रहते हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। इसमें अलग-अलग ट्रेड में अलग-अलग qualification है। Fifth class onwards Graduate होने तक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसने कहा है कि आप शिक्षा व्यवस्था को कौशल विकास से जोड़ेंगे। हमने sixth class onwards sensitize किया है और कौशल विकास की जो संस्थाएँ हैं, उनको स्कूली व्यवस्था से जोड़ा है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 3, Shri M. Mohamed Abdulla.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Thank you, Chairman Sir, for permitting me to ask a supplementary question. I want to know whether it is a fact that no report has been published analyzing the efficiency and quality of STT and RPL courses under PMKVY so far.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, I would like to point out that even in 2019 we did an impact assessment. And, it is not the case that we are not constantly evaluating the progress of our schemes and the impact of our schemes. It was found in the survey that there was a high rate of satisfaction. People who were surveyed said that it helped them gain employment, it helped them gain a new skill and it helped them rise in their organizations.

MR. CHAIRMAN: Supplementary number four, Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, my query was regarding the JSS, *Jan Sikshan Sansthan*, and the hon. Minister has already answered that in the previous supplementary question. So, I am satisfied with it.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, he is satisfied.

MR. CHAIRMAN: You can express your happiness.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, the same sentiment is echoed in the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: All right, go ahead. This will be taken as supplementary number four.

DR. V. SIVADASAN: Sir, the promotion of skill development is very essential for national development. So, the Union Government should provide financial and technological assistance to every State, irrespective of the political affiliation of the Ruling Party of the State Government. But as one goes through the document, one finds an unequal distribution of money and assistance given to the States. The hon.

Minister told us that during the last three years, 1.47 lakh and 0.26 lakh candidates have been trained and reported placed, respectively, under special projects. My question is whether the Government can provide the State-wise data of expenditure, of skill development, number of training centers and the number of students in each center.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, the hon. Member has asked a specific query on State-wise data. I shall provide that to him. But I would like to point out that there is a digital public infrastructure that has been created. It was inaugurated last year, and it is called SID, Skill India Digital Hub. And recently, the G20 Task Force in India reported that the impact of DPI in our developmental progress is huge. India has achieved in 10 years what it would have normally taken 50 years to achieve. So, on SID, an entire ecosystem is visible. More than 34 schemes of 22 Central Government Ministries are visible there. More than 95 schemes for skilling run by our State Governments are visible on that. If the hon. Member would like to see what the skilling ecosystem is doing, who the training partners are, what courses are available, etc., in his constituency, in his block, close to his village, that is also accessible to him via SID.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, as per the National Skill Development Corporation, when it comes to placement assistance after short-term training under PMKVY, 64 per cent of STT-trained and certified and 78 per cent of STT- trained-but not certified reported 'unsatisfied'. Also, around 55 per cent of the participants in this program were looking for employment and were unemployed. Only 47 per cent of STT-trained and certified respondents and 27 per cent of STT-trained-but not certified reported 'working in the domain of their STT training'. So, I want to know why the results are so low and what steps the Government is taking to improve this situation.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, I would like to say that in the third phase of PMKVY, as you know, the country was going through Covid. The kind of skilling we were doing, the training we were doing, was oriented towards Covid warriors and our laborers, who were fleeing urban centers and migrating back to their homes. That is why that particular figure for that particular phase is lower than what you might have imagined. I would again reiterate, don't just go by this data that we have put in the House. There is a larger ecosystem there. The mandate given to me, the mandate

given to our Ministry and the enormous challenge before us is, how we can re-engineer our systems, our protocols, our schemes to make them better aligned to the markets. It has to be demand driven; it has to be driven by needs of industry and, therefore, we are providing a lot of flexibility to our training partners. Earlier, in the three phases, like I mentioned, record placement was being noted. Now, people may be getting a job and that data might not be visible with us. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Question No.168.